**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या. 1212**

**(सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)**

**दाहोद में सरकारी क्षेत्र के बैंक**

**1212. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के वित्तीय निष्पादन में सुधार से दाहोद लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों को कितना लाभ हुआ है;
(ख) वर्ष 2014-15 की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सुदृढ़ स्थिति ने दाहोद में कृषि ऋणों, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा योजनाओं की प्रगति में किस प्रकार योगदान दिया है; और
(ग) विगत वित्त वर्ष के दौरान उक्त जिले में बैंक शाखाओं के विस्तार और बैंकिंग सेवाओं में सुधार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल निवल लाभ किस प्रकार परिलक्षित हुआ है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।**

**(श्री हर्ष मल्होत्रा)**

**(क):** वित्तीय सेवा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, 30 जून, 2017 तक दाहोद जिले में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की कुल जमा राशि 2372.22 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च, 2025 तक यह 4832.67 करोड़ रुपये हो गई। 2017 से 2025 की अवधि के दौरान कुल जमा राशि में वृद्धि दाहोद जिले में बढ़ी हुई वित्तीय बचत का संकेत देती है।

इसी प्रकार, 30 जून, 2017 तक दाहोद जिले में कुल अग्रिम 1038.92 करोड़ रुपये थे। 31 मार्च, 2025 तक यह 2642.05 करोड़ रुपये हो गया। 2017 से 2025 की अवधि के दौरान कुल अग्रिमों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो दाहोद जिले की समग्र आर्थिक कार्यकलापों को सीधे लाभ पहुँचाने वाली ऋण लेने की क्षमता में सुधार को दर्शाता है।

**(ख):** 30 जून, 2017 तक दाहोद जिले में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल कृषि ऋण (बकाया) 271.45 करोड़ रुपये था। 31 मार्च, 2025 तक यह 669.10 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि कृषि अवसंरचना और कृषि-सहायक कार्यकलापों में फसल ऋण और सावधि ऋण के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए पर्याप्त ऋण को दर्शाती है, जिससे दाहोद जिले की ग्रामीण और आदिवासी आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत बढ़ रहा है।

उपरोक्त कुल कृषि ऋणों में से, 30 जून, 2017 तक बकाया किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की राशि 171.27 करोड़ रुपये थी, जबकि 31 मार्च, 2025 तक यह 406.03 करोड़ रुपये हो गई। यह दाहोद जिले में ग्रामीण और आदिवासी आबादी के आजीविका स्रोतों को बढ़ाने और बेहतर बनाने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रत्यक्ष योगदान को दर्शाता है।

31 मार्च, 2025 तक दाहोद जिले के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना का कुल बकाया ऋण 6.75 करोड़ रुपये है। दाहोद जिले में 31 मार्च, 2017 तक पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल बकाया ऋण 35.05 करोड़ रुपये था, जो 31 मार्च, 2025 तक बढ़कर 58.09 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि दाहोद जिले में सूक्ष्म उद्यमियों के लिए पीएसबी द्वारा मजबूत वित्तीय सहायता प्रणाली को दर्शाती है।

**(ग):** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, सरकार का प्रयास देश के सभी बसे हुए गाँवों के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट/इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बैंकिंग आउटलेट की उपलब्धता की निगरानी एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित ऐप, अर्थात् जन धन दर्शक (जेडीडी) ऐप द्वारा की जाती है। जेडीडी ऐप पर बैंकों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर, देश के कुल 6,01,328 बसे हुए गाँवों में से 6,00,813 (99.91%) गाँव 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट (बैंक शाखा/बीसी/आईपीपीबी) से कवर हैं।

पीएसबी के उपरोक्त वित्तीय मापदंडों से पता चलता है कि पीएसबी ने दाहोद जिले की आर्थिक वृद्धि और समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

*****